



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 1, 2019/आश्विन 9, 1941

No. 312]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019/ASVINA 9, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2019

(मामला सं. सीवीडी 04/2019)

विषय : मलेशिया से क्लियर फ्लोट ग्लास के आयातों के संबंध में आर्थिक सहायता-रोधी/प्रतिकारी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/14/2019-डीजीटीआर.—मै० सेंट-गोबाइन इंडिया प्रा० लि०, मै० सीसेकॉम फ्लैट ग्लास इंडिया लि०, असाही इंडिया ग्लास लि० (ए आई एस) और मै० गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लि० (जिन्हें यहां याचिकाकर्ता या आवेदक भी कहा गया है), ने मलेशिया (जिसे यहां संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “4 मि. मि. से 12 मि. मि. (दोनों शामिल) की रेंज वाले नाम मात्र मोटाई वाले क्लियर फ्लोट ग्लास” (जिन्हें यहां ‘संबद्ध वस्तु’ या विचाराधीन उत्पाद अथवा पी यू सी कहा गया है) के आयातों पर प्रतिकारिता शुल्क लागू करने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (आर्थिक सहायता प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली (जिसे यहां नियमावली भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिन्हें यहां अधिनियम भी कहा गया है) के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

आर्थिक सहायता देने का आरोप :

- याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों ने संबद्ध देश की सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराई गई कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ प्राप्त किया है जिसमें विभिन्न प्रोविंसिज और नगर पालिकाओं की सरकार शामिल हैं जिनमें उत्पादक/निर्यातक तथा अन्य ‘सार्वजनिक निकाय’ स्थित हैं। याचिकाकर्ता ने संगत कानूनों, नियमों और विनियमों तथा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध संगत सरकारी एजेंसियों तथा सार्वजनिक

निकायों की अधिसूचनाओं और अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों के निर्धारण में जिन्होंने ऐसी योजनाओं की विस्तृत जांच आयोजित की थी और प्रतिकारी योग्य आर्थिक सहायता कार्यक्रमों के अस्तित्व को समाप्त किया, का आश्रय लिया है।

परामर्शी :

3. ए एस सी एम के अनुच्छेद 13 के अनुसरण में मलेशिया सरकार के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में दिनांक 17 सितंबर, 2019 को विचार-विमर्श किए गए। मलेशिया सरकार के प्रतिनिधियों की टिप्पणियों को रिकार्ड पर लिया गया है।

सब्सिडी कार्यक्रम :

4. आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य दर्शाते हैं कि मलेशिया में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों की मलेशिया सरकार और/ या अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा बड़ी संख्या में प्रदत्त सब्सिडीज से लाभ प्राप्त किया है जैसा नीचे सूचीबद्ध है। कथित सब्सिडीज में निधियों का सीधा हस्तांतरण और निधियों या देयताओं का संभावित सीधा हस्तांतरण शामिल है; सरकारी राजस्व जो अन्यथा रूप से देय है, पूर्व निर्धारित है अथवा एकत्रित नहीं किया गया है, पर्याप्त से कम पारिश्रमिक के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान, आदि शामिल है।

I. अनुदानों के रूप में चिन्हित योजनाएं

1. प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी
2. बाजार विकास अनुदान

II. कर प्रोत्साहन के रूप में चिन्हित योजनाएं:

3. अग्रणी स्थिति
4. ईस्ट कोस्ट आर्थिक कोरीडोर में विनिर्माण और विनिर्माण संबंधित संवाओं के लिए प्रोत्साहन
5. निवेश कर भत्ता
6. त्वरित पूंजी भत्ता
7. मलेशियाई ब्रांड की प्रोन्नति के लिए दुगुनी कटौती
8. आयात शुल्क, बिक्री कर एवं उत्पाद शुल्क कर ड्रा बैक
9. बिक्री कर छूट
10. आउट सोर्सिंग विनिर्माण गतिविधियों के लिए आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
11. फालतू हिस्से पुर्जी और उपभोक्ता वस्तुओं पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
12. मशीनरी और उपकरणों पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
13. कच्ची सामग्री/ संघटकों पर आयात शुल्क से छूट
14. निर्यातों के संवर्धन के लिए दुगुनी कटौती
15. निर्यात कारगो के संवर्धन के लिए दुगुनी कटौती
16. बढ़े हुए निर्यात के लिए भत्ता
17. टैरिफ संबंधित प्रोत्साहन
18. संयंत्रों और मशीनरी के लिए भत्ता

III. निर्यात क्रेडिट और निर्यात वित्त पोषण के रूप में चिन्हित योजनाएं :

19. निर्यात ऋण पुनर्वित्त पोषण

20. क्रयकर्ता ऋण गारंटी

5. यह आरोप लगाया गया है कि उपर्युक्त योजनाएं सब्सिडाइज्ड हैं, क्योंकि उनमें संबंधित संबद्ध देशों की सरकारों या ऐसे संबंधित देशों की स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारों से जिनमें सार्वजनिक निकाय शामिल हैं, वित्तीय अंशदान है और प्राप्तकर्ताओं को लाभ प्रदान करना शामिल है। उन पर कुछ विशेष उद्यमों या उद्यमों के समूह और/ या उत्पादों और/ या क्षेत्र तक सीमित होने और इसलिए विशिष्ट और उसके बराबर होने का आरोप है उन पर कुछ मामलों में आयातित वस्तुओं की तुलना में घरेलू वस्तुओं के प्रयोग पर अवलंबित होने और/ या निर्यात निष्पादन पर अवलंबित होने का भी आरोप है।
6. उत्पादकों/निर्यातकों से किसी अन्य सब्सिडी योजना जो उनके द्वारा प्राप्त की गई हो सकती है, के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य सब्सिडीज की, जो विद्यमान हो सकती है, जांच करने का अधिकार संरक्षित रखते हैं जो जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा और प्राप्त की गई पाई जाती हैं।

क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप :

7. याचिकाकर्ताओं ने घरेलू उद्योग को “क्षति” से संबंधित विभिन्न पैरामीटरों पर सूचना उपलब्ध कराई है जैसाकि नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य “प्रथम दृष्ट्या” साक्ष्य दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से उचित सब्सिडाइज्ड आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

जांच की शुरुआत :

8. प्राधिकारी ने पाया है संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात पर प्रतिकारी सब्सिडी की विद्यमानता के प्रथम दृष्ट्या प्रमाण हैं और ऐसे सब्सिडाइज्ड आयात अपनी मात्रा और कीमत प्रभावों के जरिए घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति उत्पन्न कर रहे हैं और अधिक ज्यादा महत्व क्षति की आशंका का कारण बन रहे हैं।
9. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी, एतद द्वारा उपरोक्त नियमावली के नियम 6 की शर्तों में कथित सब्सिडी और घरेलू उद्योग को परिणामस्वरूप होने वाली उल्लेखनीय क्षति और क्षति की आशंका के संबंध में जांच आरंभ करते हैं ताकि कथित सहायता की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और प्रतिकारी शुल्क की राशि की सिफारिश की जा सके, जो यदि लगाई जाती तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होती।

घरेलू उद्योग :

10. याचिकाकर्ताओं के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं के केवल पांच उत्पादक हैं। विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के रूप में मै० सेंट-गोबाइन इंडिया प्रा० लि०, मै० सीसेकॉम फ्लैट ग्लास इंडिया लि०, असाही इंडिया ग्लास लि० (ए आई एस) और मै० गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लि० द्वारा आवेदन दायर किया गया है चूंकि याचिकाकर्ता भारत में विचाराधीन उत्पाद के 85 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं, याचिकाकर्ता शर्तों को संतुष्ट करते हैं और नियमावली के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग स्थापित हैं।

विचाराधीन उत्पाद :

11. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) है
“ 4 मि. मि. से 12 मि. मि. (दोनों शामिल) की रेंज में नाम मात्र मोटाई वाला क्लियर फ्लोट ग्लास” है (बी आई एस 14900 : 2000 यहां इसके बाद “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के अनुसार नाम मात्र मोटाई होने के कारण ।
12. फ्लोट ग्लास में सामान्य ग्लास निर्माण कच्ची सामग्री प्रयुक्त होती है, आमतौर पर इसमें रेत, सोडा एश (सोडियम कार्बोनेट) डोलोमाइट, साल्ट केक (सोडियम सल्फेट) आदि शामिल होते हैं। अन्य सामग्रियों को रंजक, शोधक एजेंट अथवा ग्लास की भौतिक और रसायनिक विशेषताओं को समायोजित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कच्ची सामग्रियों को बैच मिक्सिंग प्रक्रिया में मिश्रित किया जाता है तब एक नियंत्रित अनुपात में उपयुक्त कलेट (अवशिष्ट ग्लास) के साथ फर्नेस में भरा जाता है जहां इसे लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। एक बार

पिघलने पर, ग्लास का तापमान एक सजातीय विशिष्ट गुरुत्व को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर किया जाता है।

13. उत्पाद का मुख्य प्रयोग निर्माण, रेफ्रिजरेटर, शीशा और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री आदि में किया जाता है। उत्पाद एक उत्तम गुणवत्ता वाला ग्लास है। इसकी आंतरिक शक्ति, उच्च ऑप्टिकल स्पष्टता, विरूपण युक्त चिकनी सतह, आदि के कारण विभिन्न प्रयोजनों के लिए उत्पाद के अनुप्रयोगों में वृद्धि हुई है।
14. पी यू सी को अध्याय शीर्ष 70 “ग्लास और ग्लासवेयर” के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 8 अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 70051090 है, हालांकि इसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के विभिन्न उप शीर्षों जैसे 7003, 7004, 7005, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018 और 7020 के तहत वर्गीकृत और आयातित किया जा रहा है।

समान वस्तु :

15. याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं समान वस्तु हैं। संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित क्लियर फ्लोट ग्लास अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रसायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विशिष्टताएं, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की शर्तों में तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए, इन्हें नियमों के तहत ‘समान वस्तु’ माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के ‘समान वस्तु’ के रूप में माना जा रहा है।

शामिल देश :

16. वर्तमान जांच मलेशिया में विचाराधीन उत्पाद के कथित आर्थिक सहायता प्राप्त करने (सिन्सडाइजेशन) के संबंध में है।

जांच की अवधि (पी ओ आई)

17. वर्तमान जांच के दौरान जांच की अवधि अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 (12 महीने) है। तथापि, क्षति जांच अवधि में पिछले तीन वर्षों के आंकड़े अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016, 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 और पी ओ आई की अवधि शामिल है।

सूचना प्रस्तुत करना :

18. संबद्ध देश में निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग नीचे दिए गए पते पर निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं बताए गए तरीके से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

महानिदेशक

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य विभाग

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

19. कोई अन्य पक्षकार भी निर्धारित प्रपत्र में और नीचे दी गई समय सीमा में निर्धारित किए गए तरीके में जांच से संबंधित निवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

20. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना इस जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (दिनों 40) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे, इस जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना मूल प्रतियों और सॉफ्ट प्रतियों में अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-
23. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के प्रत्येक की दो (2) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
24. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना अंतर्निहित होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
27. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
28. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण :

29. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2019

(Case No. CVD 04/2019)

Subject: Initiation of Anti-Subsidy/countervailing investigation concerning imports of Clear Float Glass from Malaysia.

F. No. 6/14/2019–DGTR.—M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd., M/s Sisecam Flat Glass India Ltd., Asahi India Glass Limited (AIS) and M/s Gold Plus Glass Industry Limited (herein after also referred to as the Petitioners or Applicants) have filed an application before the Designated Authority(herein after also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of injury) Rules as amended from time to time(herein after also referred to as the Rules)for imposition of Countervailing on imports of “Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive)” (hereinafter also referred to as ‘subject goods’ or ‘product under consideration or PUC’) originating in or exported from Malaysia (hereinafter also referred to as subject country).

Allegation of Subsidization

- The petitioners have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from the actionable subsidies provided at various levels by the Government of the subject country, including the government of different provinces and Municipalities in which producers/exporters are located, and other ‘Public bodies’. The petitioner has relied upon the relevant Laws, Rules and Regulations and other Notifications of the relevant Government Agencies and Public Bodies as available in the public domain and in the determination of other investigating Authorities who had conducted comprehensive investigation of such schemes and concluded existence of countervailable subsidy programs.

Consultation

- In accordance with Article 13 of the ASCM, consultations were carried out with the representatives of the Government of Malaysia on 17th September 2019 in New Delhi. The comments of representatives of the Government of Malaysia have been taken on record.

Subsidy Programs

- The *prima facie* evidence provided by the applicants show that the producers and exporters of the subject goods in Malaysia have benefitted from a number of subsidies granted by the Government of Malaysia and/or other public bodies as listed below. The alleged subsidies consist of direct transfer of funds and potential direct transfer of funds or liabilities; Government revenue that is otherwise due is foregone or not collected; Provision of goods and services for less than adequate remuneration; etc.

I. Schemes Identified as Grants

- Subsidies on Natural Gas
- The Market Development grant

II. Schemes Identified as Tax Incentive

3. Pioneer Status
4. Incentive for manufacturing and manufacturing related service in East Cost Economic Corridor
5. Investment Tax Allowance
6. Accelerated Capital Allowance
7. Double deduction for promotion of Malaysian brand
8. Draw back on Import duty, Sales tax and Excise duty
9. Sales Tax Exemption
10. Exemption from Import Duty and Sales Tax for Outsourcing Manufacturing Activities.
11. Exemption from Import Duty and Sales Tax on Spares and Consumables
12. Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment
13. Exemption from Import Duty on Raw Materials/Components
14. Double Deduction for Promotion of Exports
15. Double Deduction for Promotion of Export Cargo
16. Allowance for Increased Export
17. Tariff Related Incentive
18. Allowance for plants and Machinery

III. Schemes Identified as Export Credit and Export Financing

19. Export Credit Refinancing
 20. Buyer Credit Guarantee
5. It has been alleged that the above schemes are subsidies since they involve a financial contribution from the Governments of the respective subject countries or other regional or local governments of such respective countries, including public bodies and confer benefit on the recipient (s). They are also alleged to be limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions and therefore specific and countervailable. They are also in some cases alleged to be contingent upon the use of domestic over imported goods and/or contingent upon export performance.
 6. The producers/exporters are advised to provide information with respect to any other subsidy scheme that may have been availed by them. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of investigation.

Allegation of Injury and Casual Link

7. The petitioners have furnished information on various parameters relating to 'injury' to the domestic industry as prescribed under the Rules. The evidence provided by the petitioner's *prima facie* shows that material injury to the domestic industry has been caused by the alleged subsidized imports from the subject country.

Initiation of the Investigation

8. The Authority finds that there is *prima facie* evidence of existence of countervailable subsidies on production and export of the subject goods in the subject country and such subsidized imports are causing material injury and further threat of material injury to the domestic industry through their volume and price effects.
9. In view of the above position, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged subsidization and consequent material injury and threat of injury to the domestic industry in terms of Rule 6 of the Rules *supra*, to determine the existence, degree and effect of alleged subsidization and to recommend the amount of countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Domestic Industry

10. According to the Petitioners, there are only five producers of the subject goods in India. The Application has been filed by M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd., M/s Sisecam Flat Glass India Ltd., Asahi India Glass Limited

(AIS) and M/s Gold Plus Glass Industry Limited as domestic industries of the product under consideration. Since the petitioners account for 85% of the production of the product under consideration in India, the petitioner satisfies the standing and constitutes Domestic Industry within the meaning of the Rules.

Product under Consideration

11. The product under consideration(PUC) in the present investigation is
“Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive)” the nominal thickness being as per BIS14900:2000 (hereinafter referred to as the “subject goods”.
12. Float glass uses common glass-making raw materials, typically consisting of sand, soda ash (sodium carbonate), dolomite, limestone, salt cake (sodium sulfate) etc. Other materials may be used as colourants, refining agents or to adjust the physical and chemical properties of the glass. The raw materials are mixed in a batch mixing process, then fed together with suitable cullet (waste glass), in a controlled ratio, into a furnace where it is heated to approximately 1500°C. Common flat glass furnaces are 9 m wide, 45 m long, and contain more than 1200 tons of glass. Once molten, the temperature of the glass is stabilized to approximately 1200°C to ensure a homogeneous specific gravity.
13. The product finds major uses in construction, refrigeration, mirror and automobile industries etc. The product is a superior quality of glass. Due to its inherent strength, high optical clarity, distortion free smooth surface etc., the applications of the product have been increasing for different purposes.
14. The PUC is classified under Chapter Heading 70 “Glass and glassware”. The classification at the 8-digit level is 70051090 even though the same are being classified and imported under various sub-headings like 7003, 7004, 7005, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018 and 7020 of the Customs Tariff Act, 1975.

Like Article

15. The petitioners have submitted that subject goods produced by the petitioner company and the subject goods imported from the subject country are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from subject country and that produced by the petitioner. Clear Float Glass produced by the domestic industry and imported from subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

Country involved

16. The present investigation is in respect of alleged subsidization of the product under consideration in Malaysia.

Period of Investigation (POI)

17. The period of investigation for the purpose of present investigation is from April 2018 to March 2019 (12 months). However, the injury investigation period will cover the data of previous three years, i.e., 1st April 2015 to 31st March 2016, 1st April 2016 to 31st March-2017, 1st April 2017 to 31st March 2018 and POI.

Submission of Information

18. The exporters in the subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Director General
Directorate General of Trade Remedies
Department of Commerce,
Jeevan Tara Building, 4th Floor
5, Parliament Street
New Delhi -110001.

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

20. An information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

22. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof.
23. The "confidential" or "non-confidential submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.
24. The confidential version shall contain all information, which is by nature confidential and/or other information, which the supplier of such information claims, as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
28. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

29. In terms of Rule 7(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the information or evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

30. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority